Phosphatic Fertilizer Plant at Paradeep in Orissa

*335. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that phase I and II of the phosphatic fertiliser plant situated at Paradeep in Orissa has been completed;

(b) if so, how much amount has been spent on this project so far;

(c) by when phase III of the plant is likely to be completed and what is the estimated cost of the same;

(d) whether it is also a fact that due to non-availability of raw materials in time, the plant is facing a lot of problems in production; and

(e) if so, what steps are being taken to overcome the difficulties?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BHAJAN LAL): (a) and (b) Phase-I of the project was completed on 26-2-86 while Phase-II is expected to be completed by October, 1989.

As on 28-2-1989, an amount of Rs. 424.44 crores has been spent on the two phases.

(c) There is no proposal for Phase-III of the plant.

(d) Phase-I of the project is based on imported phosphoric acid and ammonia and there have been problems in production of DAP due to difficulties in importing phosphoric acid at reasonable prices.

(e) The difficulties will be partially solved when phase-II of the propect which envisages indigenous production of phosphoric acid is completed by Paradeep Phosphates Limited. Import of phosphoric acid is also being expedited by Govt.

झांसी दूरदर्शन टावर का अन्यत्र ले जाया जाना

*336. **डा० गोविन्द दास रिछारिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को झांसी के किले के अंदर स्थापित दूरदर्शन टावर को हटाने के लिए पुरातत्व विभाग से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि दूरदर्शन टावर से किले का पुरातत्व महत्व कम हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस टावर को किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सरकार को सुझाव दिया है कि झांसी के किले के परिसर में स्थापित अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए । क्योंकि किले के अन्दर इसकी स्थापना किए जाने से स्मारक के सौंदर्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, दूरदर्शन ने ट्रांसमीटर के लिए वैकल्पिक स्थान चुनने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण किया है, क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चला है कि ट्रांसमीटर को शहर के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने से नगर के कुछ हिस्से, जो इस समय दूरदर्शन सिगनलों से कवर होते हैं, इस सुविधा से वंचित हो जाएंगे । अतः यह आवश्यक समझा गया है कि झांसी के किले में स्थापित ट्रांसमीटर से इस समय कवर होने वाले समूचे क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए नगर में एक अतिरिक्त ट्रांसमीटर स्थापित किया जाए ।

2. सातवीं योजना के अंतर्गत झांसी में एक अतिरिक्त ट्रांसमीटर स्थापित करने का चूंकि कोई प्रावधान नहीं है अतः भारतीय पुरातत्व सवक्षण को सुझाव दिया गया है कि वे झांसी के किले से ट्रांसमीटर को स्थानांतरित करने की आवश्यकता की फिर से जांच करें ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि अभी भी यह महसूस किया जाता है कि ट्रांसमीटर को स्थानांतरित किया जाना चाहिए तो इस कार्रवाई को कम से कम दूरदर्शन

विस्तार की भावी योजनाओं के अंतर्गत नगर में अतिरिक्त ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए धनराशि के उपलब्ध होने तक स्थगित करना आवश्यक होगा ।

Assistance provided by NCDC to various Units of Madhya Pradesh

*337. SHRI PRITHIBI MAJHI:
SHRI AJIT P. K. JOGI:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the amount of assistance provided to various unit of Madhya Pradesh during the last three years by the National Cooperative Development Corporation for the construction of buildings of fair price shops, construction of godowns and for purchase of motor vehicles in the tribal areas;

(b) whether additional funds have been demanded by the State Government or other institutions for this purpose; and

(c) if so, by when that amount is likely to be sanctioned?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BHAJAN LAL): (a) During the last three years, the National Cooperative Development Corporation provided assistance of Rs. 187.24 lakhs for the construction of godowns and for purchase of motor vehicles by cooperatives in the tribal areas.

(b) and (c) NCDC has taken up the question of early sanction of Rs. 29.49 lakhs which has been proposed by the State Government for the above purposes.

भोपाल में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज लेबोरेटरी का स्थापित किया जाना

*338. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस लेबोरेटरी की स्थापना के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उपर्युक्त लेबोरेटरी को कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) उपर्युक्त लेबोरेटरी पर अब तक कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी हां, भोपाल स्थित भूमि को ले लिया गया है और एक अस्थाई स्थल कार्यालय की स्थापना कर दी गई है तथा भूमि के कन्टूर सर्वे और भूमि के अन्दर के जल स्तर के सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है । भवन के मांडल को अंतिम रूप दिया गया है तथा प्रयोगशाला के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन०डी०डी०बी०) को ठेका दिया गया है । खाद्य कृषि संगठन के सलाहकारों ने भी प्रायोजना का निरीक्षण किया है और प्रयोगशाला की विशिष्टता तथा उसे स्थापित करने से संबंधित कार्य को अंतिम रूप दे दिया है । भवन के निर्माण के लिए नक्शा पहले ही तैयार कर लिया गया है ।

(ख) दिसम्बर, 1991,

(ग) 405 लाख रु. ।

Poverty alleviation programmes

*338-A. SHRI SHANKAR SINH VAGHELA:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2016 given in the Rajya Sabha on the 12th May, 1988 and state;

(a) whether the impact of poverty alleviation programme is assessed through Concurrent Evaluation and other Studies in the absence of the estimates regarding persons below poverty line after the National Sample Survey of 1983-84; and

(b) the specific methodology of Concurrent Evaluation and also of other studies; how these are done in the absence of Sample Survey and how the poverty alleviation progress is calculated from the

@Previously Starred Question 279 transferred from the 14th March, 1989.